

Need to frame a policy for overall development of villages falling under forest area in the country particularly in Bahraich, Uttar Pradesh-Laid

डॉ. आनन्द कुमार गोंड (बहराइच) : मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के बहराइच सहित देश के अनेक राज्यों के उन ग्रामीण इलाकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वन क्षेत्र के भीतर अथवा वन सीमा के समीप स्थित हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, पेयजल तथा विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। स्थानीय प्रशासन एवं पंचायतों द्वारा विकास कार्य आरंभ किए जाने पर कई बार स्थानीय वन विभाग की ओर से आपत्तियाँ, देरी अथवा कार्य रोकने जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे जनजीवन अत्यंत प्रभावित होता है। वन क्षेत्र की भौगोलिक कठिनाइयों, प्रशासनिक स्पष्टता के अभाव तथा विभागीय समन्वय की कमी के कारण इन गाँवों में विकास वर्षों से ठहर सा गया है। आदिवासी, वन निवासी, गरीब तथा पिछड़े वर्गों के हजारों परिवार अब भी आवश्यक सेवाओं से वंचित हैं, जिससे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन- स्तर पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मेरा आग्रह है कि वन क्षेत्रों से जुड़े इन ग्रामीण इलाकों के समग्र विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष नीति/शासनादेश शीघ्र जारी किया जाए, जिससे इन गाँवों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराई जा सकें।